

Soil Health, Traditional Farming and Sustainable Agriculture



Shri Ram Nath Thakur, Union Minister of State for Agriculture and Farmers' Affairs launched Khet Bachao Abhiyan in Alwar district under the occasion of agricultural seminar at Bagad Rajput village. The campaign is based on the principle of protecting soil health, which is achieved through scientific reduction in the use of chemical fertilizers and by promoting traditional farming practices. This initiative is also connected with the vision of Viksit Bharat 2047, in which healthy farms and healthy human bodies are an integral part of the development of the nation. The campaign began on 1 June and will continue across the country till 30 June.

The Campaign has some key highlights, including:

- Campaign was started in Alwar district, at Bagad Rajput village.
- Shri Ram Nath Thakur, Minister of Union, reminded that the soil health is closely linked to human health.
- The campaign is to decrease overuse of chemical fertilizer.
- The traditional and sustainable farming practices are being promoted among farmers.
- Farmers have been advised at the field level by the agricultural officers to be aware of the issue.
- The campaign also encourages the promotion of government initiatives which can help boost the incomes of farmers.

Why Khet Bachao Abhiyan is important?

Soil Health and Human Health

- Soil fertility can be compromised by excessive use of chemical fertilizers.
- The poor soil health can impact agricultural productivity.
- Affecting human health, due to crops grown on unhealthy soil.
- Safe and nutritious food is produced by healthy farms.

Return to Traditional Farming

- Farmers can maintain soil fertility using traditional farming practices.
- Alternative information to chemical fertilizers can help sustainable farming.
- Farm income and ecological balance can be enhanced through practices like vermicompost, beekeeping and use of organic inputs.

Role of Agricultural Institutions and Experts

- Shri Karan Narendra Agriculture University, Jobner and Indian Council of Agricultural Research, ATARI Jodhpur gave details regarding the objective and activities of the campaign
- Also, experts shared information regarding the agricultural schemes and farmer-oriented measures.
- Agricultural officers were persuaded to conduct the scientific guidance of farmers for the transition of chemical farming to traditional farming.

Farmers' Experiences

- Shri Mahendra Kumar Saini, progressive farmer of Gujuki village shared that he earned more after engaging in traditional agriculture along with the modern methods of farming.
- He was provided with subsidy for schemes like poly house, mulching and vermicompost.
- Shri. Nawab Singh, a progressive farmer, shared his experience of how bee keeping has enabled him to boost his income.
- The activity of beekeeping was mentioned as a co-agricultural activity which has the potential to generate extra income and contribute to environmental protection.

RAS Exam Relevance

- It is news that will be important in the context of agriculture, sustainable development, soil health, government campaigns, farmer welfare, and environmental conservation.
- It links agriculture, health, ecology and income generation.

- Can be used in the answers to the following points of the RAS Mains paper: Sustainable Agriculture, Organic Agriculture, Rural development and farmers income.

Conclusion

The Khet Bachao Abhiyan is a significant move towards sustainable agriculture and soil protection. The campaign will help to foster traditional farming practices, minimize chemical fertilizers, and spread awareness by engaging agricultural officers to safeguard agricultural productivity and human health. It also contributes to the bigger vision of Viksit Bharat 2047, with the help of healthy agriculture and empowered farmers.

MCQs

MCQ 1 Given that Khet Bachao Abhiyan has been introduced in Alwar district, which of the following statements are correct?

1. The campaign was initiated at Bagad Rajput village of Alwar district.
2. It is intended to encourage over-fertilising for increased crop yields.
3. The campaign is connected to concept of healthy farms and healthy human bodies.

Which of the statements given above is/are correct?

- A. 1 and 2 only
- B. 1 and 3 only
- C. 2 and 3 only
- D. 1, 2 and 3

Answer: B. 1 and 3 only

Explanation : The Campaign was started at Bagad Rajput village in Alwar district, and it emphasizes the link between soil health and human health. Does not encourage over-fertilization. Instead, it focuses on limiting chemical fertilizers in a scientific manner and reverting to traditional farming methods.

MCQ 2: The Khet Bachao Abhiyan (1 June onwards) will be taking place throughout the country until:

- A. 15 June
- B. 20 June
- C. 30 June

D. 31 July

Answer: C. 30 June

Explanation : The campaign was started on 1 June and will run nationally until 30 June. The aim of this is to educate the farmers about the importance of soil health, traditional farming and the scientific method of reducing chemical fertilizers.

MCQ 3: Progressive farmer Shri Nawab Singh pointed out that one of the co-agricultural activities which can boost farmers income and help environmental conservation is which of the following?

A. Poly house farming

B. Beekeeping

C. Mulching

D. Drip irrigation

Answer: B. Beekeeping

Explanation : Shri Nawab Singh, the progressive farmer, shared his experience on how he had raised his income by bee keeping. It was said that it is a co-agricultural activity which will bring extra income to farmers and at the same time environmental conservation.

3 मृदा स्वास्थ्य, परम्परागत खेती और टिकाऊ कृषि

केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्यमंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने अलवर जिले के ग्राम बगड़ राजपूत में कृषि गोष्ठी के अवसर पर खेत बचाओ अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से कम करने और परम्परागत खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। यह पहल विकसित भारत 2047 की दृष्टि से भी जुड़ी हुई है, जिसमें स्वस्थ खेत और स्वस्थ मानव शरीर को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। यह अभियान 1 जून से शुरू हुआ और देशभर में 30 जून तक चलेगा।

अभियान की प्रमुख बातें

- यह अभियान अलवर जिले के ग्राम बगड़ राजपूत में शुरू किया गया।
- केंद्रीय राज्यमंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य का मानव स्वास्थ्य से सीधा संबंध है।
- अभियान का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है।
- किसानों के बीच परम्परागत और टिकाऊ खेती की पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे खेत स्तर पर किसानों को इस विषय में जागरूक करें।
- यह अभियान किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को भी प्रोत्साहित करता है।

खेत बचाओ अभियान क्यों महत्वपूर्ण है?

मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य

- रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता प्रभावित हो सकती है।
- कमजोर मृदा स्वास्थ्य कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।
- अस्वस्थ मिट्टी में उगाई गई फसलें मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।
- सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के उत्पादन के लिए स्वस्थ खेत आवश्यक हैं।

परम्परागत खेती की ओर वापसी

- किसान परम्परागत खेती के माध्यम से मृदा की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं।
- रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों की जानकारी टिकाऊ खेती में सहायता कर सकती है।
- वर्मी कम्पोस्ट, मधुमक्खी पालन और जैविक आदानों के उपयोग जैसी गतिविधियों से किसानों की आय और पारिस्थितिक संतुलन दोनों में सुधार हो सकता है।

कृषि संस्थानों और विशेषज्ञों की भूमिका

- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अटारी जोधपुर ने अभियान के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी।
- विशेषज्ञों ने कृषि योजनाओं और किसान-केंद्रित उपायों के बारे में भी जानकारी साझा की।
- कृषि अधिकारियों से कहा गया कि वे किसानों को रासायनिक खेती से परम्परागत खेती की ओर वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करें।

किसानों के अनुभव

- ग्राम गुजूकी के प्रगतिशील किसान श्री महेन्द्र कुमार सैनी ने बताया कि परम्परागत खेती के साथ आधुनिक कृषि विधियों को अपनाकर उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- उन्हें पॉली हाउस, मल्लिचंग और वर्मी कम्पोस्ट जैसी योजनाओं के लिए सरकारी सहयोग प्राप्त हुआ।
- प्रगतिशील किसान श्री नवाब सिंह ने बताया कि मधुमक्खी पालन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि हुई है।
- मधुमक्खी पालन को एक सह-कृषि गतिविधि बताया गया, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल सकता है।

आरएस परीक्षा की दृष्टि से महत्त्व

- यह समाचार कृषि, टिकाऊ विकास, मृदा स्वास्थ्य, सरकारी अभियान, किसान कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
- यह कृषि, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और आय सृजन को आपस में जोड़ता है।
- आरएस मुख्य परीक्षा में टिकाऊ कृषि, जैविक कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों की आय से जुड़े उत्तरों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

खेत बचाओ अभियान टिकाऊ कृषि और मृदा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभियान परम्परागत खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और कृषि अधिकारियों की भागीदारी से किसानों में जागरूकता फैलाने में सहायक होगा। इससे कृषि उत्पादकता और मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी। यह स्वस्थ कृषि और सशक्त किसानों के माध्यम से विकसित भारत 2047 की व्यापक दृष्टि में भी योगदान देता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न 1

अलवर जिले में शुरू किए गए खेत बचाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह अभियान अलवर जिले के ग्राम बगड़ राजपूत में शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य अधिक फसल उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
- यह अभियान स्वस्थ खेत और स्वस्थ मानव शरीर की अवधारणा से जुड़ा हुआ है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: B. केवल 1 और 3

व्याख्या: यह अभियान अलवर जिले के ग्राम बगड़ राजपूत में शुरू किया गया और इसमें मृदा स्वास्थ्य तथा मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध पर बल दिया गया। यह रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसके स्थान पर यह रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से सीमित करने और परम्परागत खेती की ओर लौटने पर केंद्रित है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 2

1 जून से शुरू हुआ खेत बचाओ अभियान देशभर में कब तक चलेगा?

- A. 15 जून
- B. 20 जून
- C. 30 जून
- D. 31 जुलाई

उत्तर: C. 30 जून

व्याख्या: यह अभियान 1 जून से शुरू हुआ और देशभर में 30 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य, परम्परागत खेती और रासायनिक उर्वरकों को वैज्ञानिक तरीके से कम करने के महत्त्व के बारे में जागरूक करना है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 3

प्रगतिशील किसान श्री नवाब सिंह ने किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में सहायक किस सह-कृषि गतिविधि का उल्लेख किया?

- A. पॉली हाउस खेती
- B. मधुमक्खी पालन
- C. मल्लिचंग
- D. बूंद-बूंद सिंचाई

उत्तर: B. मधुमक्खी पालन

व्याख्या: प्रगतिशील किसान श्री नवाब सिंह ने बताया कि मधुमक्खी पालन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसे एक सह-कृषि गतिविधि बताया गया, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है और साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है।

Digital Financial Management, Treasury Reforms and Cyber Security



DIGITAL FINANCIAL MANAGEMENT, TREASURY REFORMS AND CYBER SECURITY

Chief Secretary Shri V. Srinivas said, that the Integrated Financial Management System (IFMS) 3.0 is contributing significantly in rendering the financial administration of Rajasthan more transparent, accountable, traceable and citizen centric. The state government is doing all it can to build the capacity of technology-based good governance. IFMS 3.0 is becoming more powerful to facilitate the implementation of schemes, payment processing, financial monitoring and account management. The system is designed to modernize the treasury and financial management system in Rajasthan as per the vision of the Government for governance under Shri Bhajanlal Sharma, the Chief Minister. Special focus is being given to artificial intelligence-based facilities, cyber security, regular training and user-friendly digital systems.

The most important changes in IFMS 3.0 are highlighted below:

- IFMS 3.0 will enhance the financial management system of Rajasthan.
- It seeks to increase transparency, accountability, traceability and citizen-centricity of the financial system.
- The state treasury system will be modernized, solid and trustworthy.
- Modern technology will be used in the implementation of the scheme, payments, financial monitoring and accounting.
- The system will be encouraged to use artificial intelligence based features.

Accessible user-friendly modules will be created.

- Officials and staff will be provided with regular training and capacity building programmes.

- Security in the digital financial system will continue to be a key priority.

Importance of IFMS 3.0

Strengthening Financial Governance

- IFMS 3.0 is aligned with technology based good governance.
- It aids in enhancing government financial transparency.
- It provides greater transparency for financial transactions and treasury processes.
- It can enhance the cooperation between departments.
- It helps to implement the financial modules in time.
- The use of Artificial Intelligence and modern technology is encouraged in the system.

IFMS 3.0 will incorporate AI enabled facilities.

- Today's modern digital tools will facilitate financial processes.
- Technology will enhance monitoring, payment and accounting procedures.
- Examples of good practice across various districts will be shared to ensure good practice is implemented.
- Tackling cyber security and data protection issues. Addressing cyber security and data protection concerns.
- Data protection is crucial for digital financial systems.
- The Chief Secretary ordered departments to have robust cyber security measures in place.
- Regular security audits will be carried out to detect and minimise digital risks.
- Officials will be made more aware of cyber threats.
- Departments will need to be careful and responsible in keeping the data secure and reliable.

Role of Training and Capacity Building

- Drawing and Disbursing Officers, District Level Officers and related staff will be given regular training.
- Through capacity building programmes, officials will be able to effectively utilize IFMS 3.0.
- System training will increase the efficiency and user-friendliness of the system.
- Financial administration at the field level will be enhanced through the acquisition of better technical understanding.

Implementation and Institutional Support

- Principal Secretary, Finance Department Shri Vaibhav Galriya said that IFMS 3.0 is a significant project to modernise and make the financial system transparent in the state.
- There are plans to connect various departments and schemes with the digital platform in a phased manner.
- Effective implementation of financial system like SNA SPARSH.
- Other states are also studying financial management system in Rajasthan.
- Shri Manish Shukla, Additional Director, IFMS, gave a detailed presentation about IFMS 3.0 modules, treasury management, revenue management system, help desk and support system, SNA SPARSH and Cyber Security arrangements.

RAS Exam Relevance

- This news is significant for governance, public finance, e-governance, reforms in treasury, transparency and cyber security.
- It can be used in good governance, administrative reforms, digital governance and financial accountability answers for RAS Mains.
- It is also linked to themes such as citizen-oriented governance, artificial intelligence in government, and safe digital government infrastructures.

Conclusion

IFMS 3.0 is an important step toward modernizing Rajasthan's financial administration. It will enhance transparency, accountability, traceability and cyber security, further strengthening the treasury management and financial governance. AI powered tools, frequent training, and easy-to-use systems will improve Rajasthan's public finance system, making it more efficient, secure, and user-friendly.

MCQs

MCQ 1: In reference with IFMS 3.0 in Rajasthan, consider the following statements:

1. It seeks to increase transparency and accountability of the state's financial system.
2. This eliminates the need for cyber security measures altogether.
3. It promotes the good governance based on technology in Rajasthan.

Which of the statements given above is/are correct?

- A. 1 and 2 only
- B. 2 and 3 only

C. 1 and 3 only

D. 1, 2 and 3

Answer: C. 1 and 3 only

Explanation: With the vision of greater transparency, accountability, traceability and citizen-centric financial system in Rajasthan, the main objective of IFMS 3.0 is to create a transparent, citizen-centric and accountable financial system in the state. It also enables good governance through technology through the implementation of current technology systems in payment, financial monitoring and account management. The second statement is correct since cyber security is of prime importance in IFMS 3.0 and the importance of having robust protocols and regular security audits is strongly highlighted.

MCQ 2: Which of the following areas are associated with IFMS 3.0 in Rajasthan?

A. Treasury management, revenue management system, SNA SPARSH and cyber security

B. Forest conservation, wildlife census and eco-tourism development

C. Urban housing, metro rail planning and road construction

D. Crop insurance, seed distribution and fertilizer subsidy only

Answer: A. Treasury management, revenue management system, SNA SPARSH and cyber security

Explanation: IFMS 3.0 is related to Rajasthan's financial administration and treasury system. Its modules include treasury management, revenue management system, help desk and support system, SNA SPARSH and cyber security arrangements. It is not primarily related to forest conservation, urban transport, housing or agricultural subsidy distribution alone.

MCQ 3: Why has regular training been emphasized under IFMS 3.0?

A. To replace all district-level officers with artificial intelligence systems

B. To help officers and staff use the digital financial system effectively

C. To stop the phased digital linking of departments and schemes

D. To reduce the role of financial monitoring in government schemes

Answer: B. To help officers and staff use the digital financial system effectively

Explanation: Regular training and capacity-building programmes have been emphasized for Drawing and Disbursing Officers, district-level officers and related staff. The purpose is to make them capable of using IFMS 3.0 effectively. Training will support user-friendly implementation, better technical understanding, improved coordination and efficient financial administration at the field level

अंकीय वित्तीय प्रबंधन, कोषागार सुधार और साइबर सुरक्षा

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 राजस्थान के वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, पता लगाने योग्य और नागरिक-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। राज्य सरकार तकनीक आधारित सुशासन की क्षमता को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 योजनाओं के क्रियान्वयन, भुगतान प्रक्रिया, वित्तीय निगरानी और लेखा प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए और अधिक शक्तिशाली बन रही है। यह प्रणाली मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के शासन संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप राजस्थान की कोषागार और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुविधाओं, साइबर सुरक्षा, नियमित प्रशिक्षण और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नीचे दिए गए हैं:

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 राजस्थान की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करेगी।

यह वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही, पता लगाने की क्षमता और नागरिक-केंद्रितता को बढ़ाना चाहती है।

राज्य की कोषागार प्रणाली को आधुनिक, मजबूत और विश्वसनीय बनाया जाएगा।

योजनाओं के क्रियान्वयन, भुगतान, वित्तीय निगरानी और लेखांकन में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सुगम उपयोगकर्ता-अनुकूल मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे।

अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।

डिजिटल वित्तीय प्रणाली में सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता बनी रहेगी।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 का महत्व

वित्तीय शासन को मजबूत बनाना

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 तकनीक आधारित सुशासन के अनुरूप है।

यह सरकारी वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायता करती है।

यह वित्तीय लेन-देन और कोषागार प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाती है।

यह विभागों के बीच सहयोग को बेहतर बना सकती है।

यह वित्तीय मॉड्यूलों को समय पर लागू करने में सहायता करती है।

प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुविधाओं को शामिल किया जाएगा।

आज के आधुनिक डिजिटल उपकरण वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे।

तकनीक निगरानी, भुगतान और लेखांकन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाएगी।

विभिन्न जिलों में अपनाई गई अच्छी कार्यप्रणालियों के उदाहरण साझा किए जाएंगे, ताकि श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को लागू किया जा सके।

साइबर सुरक्षा और आंकड़ा संरक्षण से जुड़ी चिंताओं का समाधान

डिजिटल वित्तीय प्रणालियों के लिए आंकड़ा संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य सचिव ने विभागों को मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए।

डिजिटल जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित सुरक्षा लेखा-परीक्षण किए जाएंगे।

अधिकारियों को साइबर खतरों के प्रति अधिक जागरूक बनाया जाएगा।

आंकड़ों को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए विभागों को सावधान और जिम्मेदार रहना होगा।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की भूमिका

आहरण और वितरण अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 का प्रभावी उपयोग कर सकेंगे।

प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण से प्रणाली की दक्षता और उपयोगकर्ता-अनुकूलता बढ़ेगी।

बेहतर तकनीकी समझ प्राप्त होने से क्षेत्र स्तर पर वित्तीय प्रशासन बेहतर होगा।

क्रियान्वयन और संस्थागत सहयोग

वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने कहा कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 राज्य की वित्तीय प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

विभिन्न विभागों और योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल मंच से जोड़ने की योजना है।

एसएनए स्पर्श जैसी वित्तीय प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अन्य राज्य भी राजस्थान की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अतिरिक्त निदेशक श्री मनीष शुक्ला ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 के माँड्यूलों, कोषागार प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन प्रणाली, सहायता केंद्र और सहयोग प्रणाली, एसएनए स्पर्श तथा साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

आरएएस परीक्षा की दृष्टि से महत्त्व

यह समाचार शासन, सार्वजनिक वित्त, ई-शासन, कोषागार सुधार, पारदर्शिता और साइबर सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।

आरएएस मुख्य परीक्षा में सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन और वित्तीय जवाबदेही से जुड़े उत्तरों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

यह नागरिक-केंद्रित शासन, शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षित डिजिटल सरकारी अवसंरचना जैसे विषयों से भी जुड़ा हुआ है।

निष्कर्ष

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 राजस्थान के वित्तीय प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही, पता लगाने की क्षमता और साइबर सुरक्षा को बढ़ाएगी तथा कोषागार प्रबंधन और वित्तीय शासन को और मजबूत करेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, नियमित प्रशिक्षण और सरल उपयोग वाली प्रणालियां राजस्थान की सार्वजनिक वित्त प्रणाली को अधिक दक्ष, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएंगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न 1

राजस्थान में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह राज्य की वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना चाहती है।
- यह साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर देती है।
- यह राजस्थान में तकनीक आधारित सुशासन को बढ़ावा देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: C. केवल 1 और 3

व्याख्या: राजस्थान में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, पता लगाने योग्य और नागरिक-केंद्रित वित्तीय प्रणाली के दृष्टिकोण के साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 का मुख्य उद्देश्य राज्य में पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह वित्तीय प्रणाली बनाना है। यह भुगतान, वित्तीय निगरानी और लेखा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकी प्रणालियों के क्रियान्वयन के माध्यम से तकनीक आधारित सुशासन को भी सक्षम बनाती है। दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 में साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है और मजबूत प्रोटोकॉल तथा नियमित सुरक्षा लेखा-परीक्षण के महत्त्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है।

हिंदी रूपांतरण नीचे दिया गया है:

बहुविकल्पीय प्रश्न 2: राजस्थान में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 से निम्नलिखित में से कौन-से क्षेत्र जुड़े हुए हैं?

- A. कोषागार प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन प्रणाली, एसएनए स्पर्श और साइबर सुरक्षा
- B. वन संरक्षण, वन्यजीव गणना और पर्यावरणीय पर्यटन विकास
- C. शहरी आवास, महानगर रेल योजना और सड़क निर्माण
- D. केवल फसल बीमा, बीज वितरण और उर्वरक अनुदान

उत्तर: A. कोषागार प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन प्रणाली, एसएनए स्पर्श और साइबर सुरक्षा

व्याख्या: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 राजस्थान के वित्तीय प्रशासन और कोषागार प्रणाली से संबंधित है। इसके मॉड्यूल में कोषागार प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन प्रणाली, सहायता केंद्र और सहयोग प्रणाली, एसएनए स्पर्श तथा साइबर सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल हैं। यह मुख्य रूप से वन संरक्षण, शहरी परिवहन, आवास या केवल कृषि अनुदान वितरण से संबंधित नहीं है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 3: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षण पर बल क्यों दिया गया है?

- A. सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों से बदलने के लिए
- B. अधिकारियों और कर्मचारियों को अंकीय वित्तीय प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए
- C. विभागों और योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अंकीय मंच से जोड़ने की प्रक्रिया रोकने के लिए
- D. सरकारी योजनाओं में वित्तीय निगरानी की भूमिका कम करने के लिए

उत्तर: B. अधिकारियों और कर्मचारियों को अंकीय वित्तीय प्रणाली का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए

व्याख्या: आहरण और वितरण अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य उन्हें एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाना है। प्रशिक्षण से उपयोगकर्ता-अनुकूल क्रियान्वयन, बेहतर तकनीकी समझ, बेहतर समन्वय और क्षेत्र स्तर पर दक्ष वित्तीय प्रशासन को सहायता मिलेगी।

Electricity Generation, Thermal Power and Energy Self-Reliance



Rajasthan has made a record in electricity generation. The Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam has generated 7,171 megawatts of power from its 23 units. This is the amount of electricity generated by the Nigam. The total capacity of these units is 7,580 megawatts. During this achievement 94.60% of the installed capacity was used. This shows that Rajasthan is using its power generation capacity better and is moving towards reducing its dependence on buying electricity from the market. The Suratgarh Thermal Power Plant played a role in this achievement. All its eight units performed well. The plant generated 2,790 megawatts of power against its capacity of 2,820 megawatts.

Key Points of the Record Power Generation

- Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam generated 7,171 megawatts of electricity from its 23 units
- The total capacity of these units is 7,580 megawatts.
- The capacity utilization was 94.60%.
- This is the electricity generation since the Nigam was formed.
- The previous record was 6,833 megawatts, which was achieved on 31 January year.
- Suratgarh Thermal Power Plants eight units generated 2,790 megawatts against a capacity of 2,820 megawatts.
- The Energy Minister congratulated the corporation for this achievement.

The Role of Suratgarh Thermal Power Plant

The Suratgarh Thermal Power Plant has played a role in Rajasthan's record electricity generation. All eight units of the plant performed strongly. They generated 2,790 megawatts of power against their capacity of 2,820 megawatts.

This performance is very important for Rajasthan. The strong performance of power units helps meet the state's electricity demand. Higher domestic generation reduces the need to buy electricity from the market. Better utilization of power plants improves the reliability of the state's energy system.

Reduced Dependence on Market Purchase

Rajasthan's electricity production has increased. Due to internal generation the need to buy electricity from the market has reduced. In May year the state had to buy around 8% of its electricity from the market. In May this year the market purchase came down to 2%.

This reduction in market purchase can reduce electricity procurement expenditure. It strengthens Rajasthan's energy self-reliance. It improves efficiency in the power sector. It supports stable electricity supply management.

Electricity Supply to Farmers

- Farmers in 26 districts of Rajasthan are now getting electricity supply in two blocks. Chittorgarh and Tonk districts have also been included in the two-block agricultural electricity supply system.
- Chittorgarh has the number of agricultural consumers with 1.01 lakh consumers. Tonk district has 34,748 consumers. Earlier this arrangement was started experimentally in Dausa and Karauli districts.
- The system will help farmers receive electricity during the day reducing difficulty in night-time irrigation. This is very important for the farmers as it will help them in their work.

Strengthening Power Infrastructure

- A high-level review was conducted to increase electricity production capacity. Directions were given to make production capacity more strong and reliable. Work is being done to increase transmission capacity in the remaining districts.
- Construction of power lines and strengthening of sub-stations is being carried out rapidly. These steps are expected to improve power supply reliability for farmers.

Importance for RAS Exam

- This news is important for Rajasthan Economy, infrastructure, energy sector and public utilities. It can be used in topics related to energy self-reliance, electricity generation, power sector reforms and agricultural support.
- It is also relevant for questions on state-level infrastructure development and government measures for farmers. This achievement is a step towards Rajasthan's power security and agricultural support system.
- Rajasthan's ever electricity generation of 7,171 megawatts reflects improved utilization of power generation capacity and stronger performance of thermal power units. The reduced dependence on market electricity purchase from 8% to 2% shows progress towards energy self-reliance.
- Along with infrastructure strengthening and daytime electricity supply to farmers this achievement is important for Rajasthan's power security and agricultural support system. The state is moving in the direction and this achievement is a big step towards a better future.

MCQs

MCQ 1: Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam created a record by generating how much electricity from its 23 units?

- A. 6,833 Megawatts
- B. 7,171 Megawatts
- C. 7,580 Megawatts
- D. 2,790 Megawatts

Answer: B. 7,171 Megawatts

Explanation: Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam generated 7,171 megawatts of electricity from 23 units having a capacity of 7,580 megawatts. This became the ever electricity generation since the formation of the Nigam.

MCQ 2: What was the capacity utilization achieved during Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam's record power generation?

- A. 82.60%
- B. 88.40%
- C. 94.60%
- D. 98.20%

Answer: C. 94.60%

Explanation: During the record power generation Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam utilized 94.60% of its installed capacity.

MCQ 3

With reference to Rajasthan's power sector achievement consider the following statements:

1. Market purchase of electricity reduced from around 8% in May year to 2% in May this year.
2. Farmers in 26 districts are getting electricity supply in two blocks.
3. Suratgarh Thermal Power Plant produced 2,790 megawatts against a capacity of 2,820 megawatts.

Which of the statements given above is/are correct?

- A. 1 And 2 only
- B. 2 And 3 only
- C. 1 And
- D. 1 2 And 3

Answer: D. 1 2 And 3

Explanation: All three statements are correct. Rajasthan's market purchase of electricity declined from around 8% in May year to 2% in May this year due to increased internal generation. Farmers in 26 districts are receiving electricity supply in two blocks. Suratgarh Thermal Power Plant also performed strongly by producing 2,790 megawatts, against its capacity of 2,820 megawatts.

बिजली उत्पादन, तापीय विद्युत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता

राजस्थान ने बिजली उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने अपनी 23 इकाइयों से 7,171 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। यह निगम द्वारा अब तक किया गया सबसे अधिक बिजली उत्पादन है।

इन इकाइयों की कुल क्षमता 7,580 मेगावाट है। इस उपलब्धि के दौरान स्थापित क्षमता का 94.60% उपयोग किया गया। यह दिखाता है कि राजस्थान अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग कर रहा है और बाजार से बिजली खरीदने पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सभी 8 इकाइयों ने अच्छा प्रदर्शन किया। संयंत्र ने 2,820 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया।

रिकॉर्ड बिजली उत्पादन के प्रमुख बिंदु

- राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने अपनी 23 इकाइयों से 7,171 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया।
- इन इकाइयों की कुल क्षमता 7,580 मेगावाट है।
- क्षमता उपयोग 94.60% रहा।
- यह निगम के गठन के बाद अब तक का सबसे अधिक बिजली उत्पादन है।
- पिछला रिकॉर्ड 6,833 मेगावाट था, जो पिछले वर्ष 31 जनवरी को प्राप्त हुआ था।
- सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र की 8 इकाइयों ने 2,820 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया।
- ऊर्जा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए निगम को बधाई दी।

सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र की भूमिका

सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र ने राजस्थान के रिकॉर्ड बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संयंत्र की सभी 8 इकाइयों ने मजबूत प्रदर्शन किया। इन्होंने 2,820 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया।

यह प्रदर्शन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली इकाइयों का मजबूत प्रदर्शन राज्य की बिजली मांग को पूरा करने में सहायता करता है। राज्य के भीतर अधिक बिजली उत्पादन होने से बाजार से बिजली खरीदने की आवश्यकता कम होती है। विद्युत संयंत्रों का बेहतर उपयोग राज्य की ऊर्जा व्यवस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

बाजार से बिजली खरीद पर निर्भरता में कमी

राजस्थान का बिजली उत्पादन बढ़ा है। आंतरिक उत्पादन बढ़ने के कारण बाजार से बिजली खरीदने की आवश्यकता कम हुई है। पिछले वर्ष मई में राज्य को अपनी लगभग 8% बिजली बाजार से खरीदनी पड़ी थी। इस वर्ष मई में बाजार से खरीद घटकर 2% रह गई।

बाजार से खरीद में यह कमी बिजली खरीद व्यय को कम कर सकती है। यह राजस्थान की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है। यह विद्युत क्षेत्र में दक्षता बढ़ाती है। यह स्थिर बिजली आपूर्ति प्रबंधन में भी सहायता करती है।

किसानों को बिजली आपूर्ति

राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को अब 2 खंडों में बिजली आपूर्ति मिल रही है। चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को भी 2 खंड वाली कृषि बिजली आपूर्ति व्यवस्था में शामिल किया गया है।

चित्तौड़गढ़ में कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है, जहां 1.01 लाख उपभोक्ता हैं। टोंक जिले में 34,748 उपभोक्ता हैं। इससे पहले यह व्यवस्था दौसा और करौली जिलों में प्रायोगिक रूप से शुरू की गई थी।

यह व्यवस्था किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करेगी, जिससे रात में सिंचाई की कठिनाई कम होगी। यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके कृषि कार्यों में सहायता मिलेगी।

बिजली अवसंरचना को मजबूत बनाना

बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। उत्पादन क्षमता को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाने के निर्देश दिए गए। शेष जिलों में प्रसारण क्षमता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

बिजली लाइनों के निर्माण और उपकेंद्रों को मजबूत बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन कदमों से किसानों के लिए बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार होने की उम्मीद है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए महत्व

यह समाचार राजस्थान अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, ऊर्जा क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग ऊर्जा आत्मनिर्भरता, बिजली उत्पादन, विद्युत क्षेत्र सुधार और कृषि सहायता से जुड़े विषयों में किया जा सकता है।

यह राज्य स्तरीय अवसंरचना विकास और किसानों के लिए सरकारी उपायों से जुड़े प्रश्नों के लिए भी प्रासंगिक है। यह उपलब्धि राजस्थान की विद्युत सुरक्षा और कृषि सहायता व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

राजस्थान का 7,171 मेगावाट का अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग और तापीय विद्युत इकाइयों के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। बाजार से बिजली खरीद पर निर्भरता 8% से घटकर 2% होना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति को दिखाता है।

अवसंरचना को मजबूत करने और किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति के साथ यह उपलब्धि राजस्थान की विद्युत सुरक्षा और कृषि सहायता व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और यह उपलब्धि बेहतर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न 1

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने अपनी 23 इकाइयों से कितनी बिजली का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाया?

- A. 6,833 मेगावाट
- B. 7,171 मेगावाट
- C. 7,580 मेगावाट
- D. 2,790 मेगावाट

उत्तर: B. 7,171 मेगावाट

व्याख्या: राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने 7,580 मेगावाट की क्षमता वाली 23 इकाइयों से 7,171 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। यह निगम के गठन के बाद अब तक का सबसे अधिक बिजली उत्पादन बना।

बहुविकल्पीय प्रश्न 2

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के रिकॉर्ड बिजली उत्पादन के दौरान क्षमता उपयोग कितना रहा?

- A. 82.60%
- B. 88.40%
- C. 94.60%
- D. 98.20%

उत्तर: C. 94.60%

व्याख्या: रिकॉर्ड बिजली उत्पादन के दौरान राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने अपनी स्थापित क्षमता का 94.60% उपयोग किया।

बहुविकल्पीय प्रश्न 3

राजस्थान के विद्युत क्षेत्र की उपलब्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- बिजली की बाजार खरीद पिछले वर्ष मई में लगभग 8% से घटकर इस वर्ष मई में 2% रह गई।
- 26 जिलों में किसानों को 2 खंडों में बिजली आपूर्ति मिल रही है।
- सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र ने 2,820 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: D. 1, 2 और 3

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। आंतरिक उत्पादन बढ़ने के कारण राजस्थान की बाजार से बिजली खरीद पिछले वर्ष मई में लगभग 8% से घटकर इस वर्ष मई में 2% रह गई। 26 जिलों में किसानों को 2 खंडों में बिजली आपूर्ति मिल रही है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत संयंत्र ने भी 2,820 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट बिजली उत्पादन कर मजबूत प्रदर्शन किया।